राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच
एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 240/2004

रंग नाथ गग्गर, पुत्र सांवरमल, निवासी कांकरोली, जिला। राजसमंद

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. पी.पी. के माध्यम से राजस्थान राज्य
2. मनमोहन सोनी पुत्र बृजमोहन सोनी,
3. श्रीमती सरला उर्फ कमला, पत्नी बृजमोहन सोनी दोनों निवासी प्रगति नगर, मदनगंज, थाना मदनगंज, जिला। अजमेर

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री तन्मय ढांड
उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री ऋषि राज सिंह राठौड़, पीपी
श्री प्यूश नाग

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन
<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टयोग्य</u>

आरक्षित तिथि ::: 25/09/2024

घोषित तिथि ::: 15/10/2024

1. माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार, इस याचिका को प्रभावी एवं शीघ्र निपटान हेतु विरासत मामलों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

2. वर्तमान याचिका सीआरपीसी की धारा 397 सहपठित 401 के तहत दायर की गई है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या 3 न्यायालय, अजमेर - कैंप-किशनगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 4/2003 में पारित दिनांक 16.12.2003 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत आरोपी-प्रतिवादी (प्रतिवादी संख्या 2 और 3) को आईपीसी की धारा 498-ए और 304-बी के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है।

3. इस मामले का सार यह है कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने 05.06.2002 को पुलिस स्टेशन मदन गंज, अजमेर में एक शिकायत/रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी बहन (मृतक प्रमिला) का विवाह 05.02.1998 को श्री मनमोहन सोनी (प्रतिवादी संख्या 2) के साथ हुआ था और उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विवाह के समय मृतका के परिवार ने प्रतिवादियों को 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) के साथ कई कीमती उपहार दिए थे। इसके बाद, 17.02.1998 को 25,000/- रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट, 1,00,000/- रुपये के साथ भेजा गया। 20,000/- (बीस हजार रुपये) की धनराशि प्रतिवादियों के पक्ष में उनके (मृतक और प्रतिवादी संख्या 2) बच्चे के जन्म के समय 29.01.2000 के आसपास आहरित की गई/दी गई।

4. शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 एक शराबी व्यक्ति था, जो विषाक्त पदार्थों के प्रभाव में था और किसी अन्य महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसने मृतका को परेशान किया।

5. 27.05.2002 को मृतक के चाचा (फूफाजी) ने शिकायतकर्ता को सूचित किया कि उसकी बहन और उसका बेटा (चिनचिन) एक दुर्घटना में घायल हो गए हैं और गंभीर रूप से जल गए हैं। लगातार, शिकायतकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की, जो आईपीसी की धारा 304 बी, 498 ए, 406, 120 बी के तहत अपराधों के लिए 228/2002 के रूप में पंजीकृत थी। उक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप, 27.05.2002 की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट (नक्शा मुआयना रिपोर्ट), मृतक और उसके बेटे का पोस्टमार्टम और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद, उक्त मुकदमे की अवधि के दौरान, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, मृतक के चाचा (श्री नटवरलाल), मृतक की जांच और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सहित कई गवाहों की मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच की गई।

6. इस पृष्ठभूमि में, शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया था कि 16.12.2003 का विवादित निर्णय तत्काल मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए बिना पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्वान वकील ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113 बी के प्रावधानों का हवाला देते हुए तर्क दिया था कि उक्त प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि दहेज की मांग पर उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होकर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उक्त अपराध को दहेज मृत्यु माना जाना चाहिए। सुविधा के लिए, संबंधित प्रावधान नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है:

> **"*113*-बी. दहेज मृत्यु के संबंध में उपधारणा -** जब प्रश्न यह हो कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी महिला की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस महिला को ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है।

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

> स्पष्टीकरण*:* इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा *304*-बी में है।"

7. इसके अलावा, राजस्थान पुलिस नियम, 1965 के नियम 6.22 का हवाला देते हुए दलील दी गई कि उक्त प्रावधानों के अनुसार, जिस व्यक्ति का मृत्युपूर्व कथन दर्ज किया जा रहा है, उसकी मानसिक स्वस्थता और सोचने की क्षमता की पुष्टि के लिए एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच अनिवार्य और बाध्यकारी है। हालाँकि, इस मामले में उक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। सुविधा के लिए उक्त प्रावधान नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है:

> ***"6.22* मृत्युकालिक कथन -** *(1)* मृत्युकालिक कथन, जहाँ तक संभव हो, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा।
>
> *(2)* यदि संभव हो, तो घोषणा करने वाले व्यक्ति की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास स्पष्ट कथन देने के लिए पर्याप्त कारण हैं, एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जाँच की जाएगी।
>
> *(3)* यदि कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो घोषणा, जब कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो, दर्ज की जाएगी। यह पुलिस विभाग और मामले से संबंधित पक्षों से असंबद्ध दो या अधिक विश्वसनीय गवाहों की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी।
>
> *(4)* यदि घायल व्यक्ति के बयान दर्ज किए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाने के जोखिम के बिना ऐसा कोई गवाह प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे दो या अधिक पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।
>
> *(5)* दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *162* के अंतर्गत, पुलिस अधिकारी को दिए गए मृत्युकालिक कथन पर, इसे करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।"

8. इसके अलावा, यह तथ्य कि एफआईआर सात दिनों की देरी से दर्ज की गई, आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अपराध से संबंधित मामलों में एक स्थायी आधार नहीं हो सकता, खासकर जब सीआरपीसी की धारा 174 के प्रावधान लागू होते हों। विद्वान वकील ने अदालत को इस तथ्य से भी अवगत कराया कि शिकायतकर्ता और गवाह (चाचा) के बयान बहुत कम समय में दर्ज किए गए थे, और उस समय वे पूरी तरह सदमे की स्थिति में थे। इसलिए, यही बात अभियुक्तों और प्रतिवादियों को बरी करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकती।

9. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि दिनांक 27.05.2002 की घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट (नक्शा मुआयना रिपोर्ट) में कहा गया है कि उक्त घटना किसी भी तरह से रसोई में नहीं हुई होगी, क्योंकि जब पुलिस अधिकारियों ने उक्त स्थान का निरीक्षण किया था तब गैस नोजल सही सलामत थे। अब तक दिए गए तर्कों के समर्थन में, शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने **गुरुचरण कुमार एवं**

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

अन्य बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 195/1992), रजनीश भटनागर बनाम उत्तराखंड राज्य (2012 क्रि.एल.जे. 3442 में रिपोर्ट) और सतीश शेट्टी बनाम कर्नाटक राज्य (एआईआर 2016 एससी 2689 में रिपोर्ट) में दिए गए अनुपातों पर भरोसा जताया।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का पुरजोर विरोध किया; **बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) एवं अन्य (2002) 6 एससीसी 650** में उल्लिखित अनुपात पर भरोसा किया, और तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। यह भी तर्क दिया गया कि किसी भी स्पष्ट अवैधता, विकृति और न्याय की विफलता के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को बरी करने के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं होगा।

11. इस मोड़ पर, विद्वान वकील ने मृतका, यानी श्रीमती प्रमिला के मृत्युपूर्व कथन पर भरोसा किया और दलील दी कि यह कथन डॉ. मनमोहन शर्मा (किशनगढ़ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर) की उपस्थिति में दर्ज किया गया था (जिसे विद्वान निचली अदालत के समक्ष प्रदर्श-पी/39-41 के रूप में प्रस्तुत अभिलेखों में दर्शाया गया है)। दलील दी गई कि उक्त मृत्युपूर्व कथन की विषयवस्तु में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कथित घटना आकस्मिक रूप से घटित हुई थी और प्रतिवादियों का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। इसके अलावा, उक्त गवाही अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं करती है।

12. इसके अलावा, **(1976) 3 एससीसी 104,** जिसका शीर्षक **मुन्नू राजा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, और (2012) 12 एससीसी 120,** जिसका शीर्षक **सुरेन्द्र कुमार बनाम पंजाब राज्य** है, में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा किया गया और यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, यदि मृत्युपूर्व कथन बिना किसी दबाव, दबाव या अनुचित प्रभाव के किया गया है, और व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से किया गया है, तो उक्त मृत्युपूर्व कथन को एक ठोस सबूत माना जाएगा। यहाँ मृतक द्वारा किया गया मृत्युपूर्व कथन उसकी स्वतंत्र इच्छा से किया गया था और उक्त तथ्य की पुष्टि संबंधित चिकित्सक द्वारा भी की गई है, इसलिए, इसे ठोस सबूत माना जाना चाहिए।

13. आगे यह तर्क दिया गया कि श्री नटवरलाल और याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता (क्रमश पी/2 और पी/3 के रूप में चिह्नित) के दिनांक 28.05.2002 के बयानों के अनुसार, जो संबंधित एसडीएम के समक्ष दर्ज किए गए

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

थे, कथित अपराधों के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया था, बल्कि उक्त बयानों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कथित घटना एक दुर्घटना थी।

14. लगातार, विद्वान वकील ने एफआईआर (प्रदर्श पी/5) की सामग्री पर भरोसा किया था और कहा था कि शिकायतकर्ता, कथित अपराध का मुख्य/चश्मदीद गवाह नहीं था, इसके अलावा, श्री नटवरलाल द्वारा दिए गए बयानों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का खंडन किया है।

15. अंत में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत उपधारणा तब लागू हो सकती है जब मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता के साथ क्रूरता या उत्पीड़न हुआ हो। फिर भी, इस मामले में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मृतका ने अपने मृत्युपूर्व बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि वह प्रतिवादियों द्वारा किसी भी प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार नहीं हुई थी। इसके अलावा, मृतका और प्रतिवादी संख्या 2 के विवाह के बाद से, किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोई शिकायत/एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

16. अभिलेखों का गहनता से अवलोकन करने, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने, बार में उद्धृत निर्णयों पर विचार करने तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस समय निम्नलिखित असंदिग्ध तथ्यों को नोट करना उचित समझता है:-

16.1 मृतका और प्रतिवादी संख्या 2 का विवाह 05.02.1998 को हुआ था और विवाह से वर्ष 2000 में एक बच्चे का जन्म हुआ था।

16.2 यह कि कथित घटना अर्थात आग लगने की घटना 27.05.2002 को हुई, जिससे मृतक को गंभीर चोटें आईं (65% जल गई) जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती प्रमिला और उनके बेटे की मृत्यु हो गई।

16.3 <u>उक्त घटना के सम्बन्ध में एफ.आई.आर./शिकायत शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा आठ दिन की देरी के बाद दिनांक 05.06.2002 को पंजीकृत कराई गई थी।</u>

16.4 27.05.2002 को ही, मृतका ने संबंधित चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में, कानून के अपेक्षित प्रावधानों का पालन करते हुए, अपना मृत्युकालिक कथन लिखा/लिखवाया/टिप्पणी किया था। <u>उक्त मृत्युकालिक कथन की विषय-वस्तु का अध्ययन करने पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतका ने स्पष्ट रूप से कहा</u>

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

था कि कथित घटना एक दुर्घटना थी और इसमें उसके ससुराल वालों की कोई संलिप्तता या दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं थे।

16.5 शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता और मुख्य गवाह श्री नटवरलाल (मृतक के चाचा-चाची) के दिनांक 28.05.2002 के बयानों में प्रतिवादियों के विरुद्ध उत्पीड़न या क्रूरता का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के अंतर्गत उपधारणा के तथ्य के संबंध में याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को प्रमाणित करने के लिए विद्वान निचली अदालत के समक्ष कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

17. अत, वर्तमान मामले के उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए कथनों को ध्यान में रखते हुए, तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन करते हुए, यह न्यायालय निम्नलिखित कारणों से वर्तमान याचिका को खारिज करना उचित समझता है:

17.1 याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क पर्याप्त सामग्री/साक्ष्यों से पुष्ट नहीं हैं।

17.2 यह न्यायालय **बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह (सुप्रा)** मामले में दिए गए कथन पर भरोसा करना उचित समझता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। इसके अतिरिक्त, किसी भी स्पष्ट अवैधता, विकृति और न्याय की विफलता के अभाव में, न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के समवर्ती निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। उक्त निर्णय से प्रासंगिक अंश नीचे दोहराया गया है:

> *"12.* हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *401* के अंतर्गत सूचक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में भिन्न निष्कर्ष पर पहुँचना न्यायोचित नहीं था। **धारा *401* की उप-धारा *(3)* में यह प्रावधान है कि धारा *401* की कोई भी बात उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि के निर्णय में परिवर्तित करने के लिए अधिकृत नहीं मानी जाएगी। उपरोक्त उप-धारा, जो पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों पर एक सीमा लगाती है और उसे दोषमुक्ति के निर्णय को दोषसिद्धि के निर्णय में परिवर्तित करने से रोकती है, स्वयं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *401* द्वारा प्रदत्त पुनरीक्षण शक्ति की प्रकृति और सीमा का सूचक है।** यदि उच्च न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से दोषसिद्धि के निर्णय में परिवर्तित नहीं कर सकता, तो वह पुनर्विचार का आदेश देकर अप्रत्यक्ष

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

> रूप से ऐसा नहीं कर सकता। **इस न्यायालय के अनेक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय सामान्यतः दोषमुक्ति के आदेश में पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिवाय उन अपवादात्मक मामलों के जहाँ लोक न्याय के हित में किसी स्पष्ट अवैधता के सुधार या घोर न्याय-हत्या की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।** उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में केवल इसलिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा क्योंकि निचली अदालत ने कानून के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाया है या साक्ष्यों के मूल्यांकन में त्रुटि की है। उन परिस्थितियों की विस्तृत सूची बनाना न तो संभव है और न ही उचित है जिनमें पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन इस न्यायालय के निर्णयों ने किसी निजी पक्ष द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *401* के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मानदंड निर्धारित किए हैं। *(*देखें **डी. स्टीफेंस बनाम नोसिबोला** की रिपोर्ट **एआईआर *1951* एससी *196*** में, **के. चिन्नास्वामी रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ़ ए.पी.की रिपोर्ट एआईआर *1962* एससी *1788*** में, **अकालु अहीर बनाम रामदेव राम** की रिपोर्ट ***(1973) 2* एससीसी *583*** में, **पाकलापति नारायण गजपति राजू बनाम बोनापल्ली पेदा अप्पादु** की रिपोर्ट ***(1975) 4* में एससीसी *477*** और **महेंद्र प्रताप सिंह बनाम सरजू सिंह** की रिपोर्ट **एआईआर *1968* एससी *707*** में दी गई है।*)*"

17.3 इसके अतिरिक्त, **मुन्नू राजा एवं अन्य (सुप्रा)** में निहित अनुपात पर भी भरोसा किया जा सकता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एआईआर **1958 एससी 22** में प्रकाशित **खुशाल राव बनाम बॉम्बे राज्य** मामले में निहित अनुपात का पालन करते हुए यह राय व्यक्त की थी कि न तो कोई विधि का नियम है और न ही विवेक का, जो इस विधि के नियम में बदल गया है कि मृत्युपूर्व दिए गए कथन पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए। उपर्युक्त अनुपात का प्रासंगिक अंश नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है:

> *"6.* उच्च न्यायालय ने माना है कि ये कथन मूलतः सत्य हैं और इनमें कोई त्रुटि नहीं है। **यह सर्वविदित है कि यद्यपि मृत्यु-पूर्व कथन को सावधानी से लिया जाना चाहिए क्योंकि कथन देने वाले से जिरह नहीं की जा सकती, फिर भी न तो कोई विधि का नियम है और न ही विवेक का कोई नियम जो इस प्रकार कठोर होकर विधि का नियम बन गया हो कि मृत्यु-पूर्व कथन पर तब तक कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए *(*देखें खुशाल राव बनाम बंबई राज्य एआईआर *1958* एससी *22*** में रिपोर्ट किया गया*)*। यह सही है कि उच्च न्यायालय ने माना है कि दो प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य मृत्यु-पूर्व कथनों की पुष्टि करते हैं, लेकिन वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा कि मृत्यु-पूर्व कथनों में कोई त्रुटि थी जिसके कारण पुष्टि की जाँच करना आवश्यक था।"

17.4 **सुरिंदर कुमार (सुप्रा)** में पारित निर्णय पर भी भरोसा किया जा सकता है, और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में, जहाँ यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो कि मृत्यु पूर्व घोषणा बिना किसी दबाव,

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के की गई/हस्ताक्षरित की गई है; किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा से, स्वेच्छा से और सच्चाई से, वही एक ठोस सबूत के रूप में स्वीकार्य होगी, और दोषसिद्धि/बरी केवल उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा के आधार पर ही हो सकती है। इसके अलावा, पुष्टिकारक सबूत जिस पर विचार किया जा सकता है वह यह है कि क्या उक्त मृत्यु पूर्व घोषणा को चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के साथ उक्त दस्तावेज़ की पवित्रता और लेखक के मन की स्थिति के संबंध में प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त अनुपात से प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुन प्रस्तुत किया गया है:

> *"17.* **कमलावा बनाम कर्नाटक राज्य *(2009) 13* एससीसी *614*** में रिपोर्ट किए गए मामले में फिर से **पनीबेन *(श्रीमती)* बनाम गुजरात राज्य *(1992) 2* एससीसी *474*** में रिपोर्ट किए गए मामले का संदर्भ दिया गया था। यह नोट किया गया था कि मृत्युपूर्व बयान दर्ज करते समय उपस्थित डॉक्टर ने इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया था कि यह उनकी उपस्थिति में दर्ज किया गया था। इस न्यायालय ने मृतक की मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में डॉक्टर से प्रमाण पत्र और समर्थन की अनुपलब्धता के संबंध में तकनीकी आपत्ति को खारिज कर दिया। यह माना गया कि इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण यह है कि यह केवल विवेक का नियम है और यह इस बात का अंतिम परीक्षण नहीं है कि मृत्युपूर्व बयान सत्य था या स्वैच्छिक।"

17.5 इसके अलावा, **हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2006) 1 एससीसी 463** में प्रतिपादित अनुपात पर भरोसा किया जा सकता है, और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी घटना को दहेज मृत्यु के दायरे में लाने के लिए कुछ निश्चित मानदंड पूरे होने चाहिए। उदाहरण के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता को दहेज की मांग के संबंध में मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। उपर्युक्त अनुपात से संबंधित अंश नीचे दोहराया गया है:

> ***"17.* दंड संहिता की धारा *304*-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-बी के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होगा कि यदि अभियोजन पक्ष दंड संहिता की धारा *304*-बी में वर्णित परिस्थितियों को स्थापित करने में सक्षम है, तो इसके अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा लागू होगी।**
>
> *18.* उपर्युक्त प्रावधानों के तत्व हैं*:*
>
> *(1)* महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट या कुछ असामान्य परिस्थितियों के कारण हुई*;*
> *(2)* ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तिथि से *7* वर्ष के भीतर हुई*;*
> *(3)* पीड़िता को उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार बनाया गया*;*

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

> *(4)* ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित होना चाहिए; और
> *(5)* यह स्थापित है कि ऐसी क्रूरता और उत्पीड़न उसकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था।"

17.6 अंत में, **गुरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2011) 12 एससीसी 408** में उल्लिखित कथन पर भरोसा किया जा सकता है, और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि किसी भी मामले में, भले ही कोई भी घटक सिद्ध न हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत कोई भी अनुमान अभियोजन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

> *"12.* हम सबसे पहले धारा *304*-बी और धारा *113*-बी के तहत की गई धारणा से संबंधित तर्क पर विचार करते हैं। धारा *304*-बी को केवल पढ़ने से ही इसकी प्रयोज्यता के लिए कई कारकों की पूर्वकल्पना की जा सकती है, वे हैं*: (i)* मृत्यु जलने या शारीरिक चोट से होनी चाहिए या सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो*; (ii)* विवाह के सात वर्षों के भीतर हुई हो*;* और *(iii)* मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया हो। इस न्यायालय ने **सुरेश कुमार सिंह ने *(2009) 17* एससीसी *243* में रिपोर्ट दी है कि यदि इनमें से एक भी तथ्य सिद्ध नहीं होता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा *113*-बी के तहत धारणा अभियोजन पक्ष के लिए उपलब्ध नहीं होगी और बचाव पक्ष पर भार नहीं आएगा।*"**

18. उपर्युक्त उद्धृत निर्णयों के सारांश और तत्काल मामले में उनकी प्रयोज्यता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि इस मामले में, यह एक स्पष्ट तथ्य है कि मृतका यानी श्रीमती प्रमिला का मृत्युपूर्व बयान उसकी स्वतंत्र इच्छा से दर्ज किया गया था, इसके अलावा, उक्त दस्तावेज को सक्षम चिकित्सा अधिकारी (डॉ. मन मोहन शर्मा) की उपस्थिति में नोट किया गया और उसकी पुष्टि की गई, जिनकी जांच भी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई थी। इसलिए, इसे राजस्थान पुलिस नियमों के नियम 6.22 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है; मृत्युपूर्व बयान की सामग्री और मुख्य गवाह (श्री नटवरलाल) और शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के बयानों में कहीं भी प्रतिवादियों द्वारा मृतका से दहेज की मांग या उत्पीड़न के आरोपों का उल्लेख नहीं है; इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में अनुचित देरी हुई है; और अंत में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले के महत्वपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर दिनांक 16.12.2003 के निर्णय पारित करते समय पहले ही विचार किया जा चुका है। अत, उक्त आदेश किसी भी प्रकार की मनमानी या अवैधता से मुक्त है।

19. उपर्युक्त तथ्यों, टिप्पणियों और पूर्वोक्त नियमों के मद्देनजर, वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण, इसे खारिज किया जाता है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाएगा।

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)

20. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान याचिका की अवधि के दौरान विद्वान विचारण न्यायालय से मंगाए गए अभिलेख वापस भेजें।

(समीर जैन), जे

दीपक/3

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(29/05/2025 को 02:47:02 बजे डाउनलोड किया गया)